लिये किस औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती । बहरहाल, इस प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, विदेशी सहयोग आदि के लिये मंजूरियां दी गई हैं। 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे 7-7 प्रस्तावों को मंजरी दी गई है । कार्यान्वित होने पर मध्य प्रदेश में इन यूनिटों में 1317 व्यक्तियों को और उत्तर प्रदेश में 870 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। अनुमान है कि 5 वर्ष की अवधि में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से क्रमश: लगभग 1292 करोड़ रुपये और 650 करोड़ रु० का निर्यात किया जायेगा ।

Raising the capital investment, in Ice-cream manufacture industry

3614. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is being considered to raise the quantum of basic capital investment in the Ice-cream manufacturing industries of the country;

(b) if so, what is the proposed quantum of maximum capital investment in case of each of the industrial units:

(c) whether it has also been proposed to give exemption to such Ice cream manufacturers whose capital investment is to be raised to sell upto 50 per cent of their total production in the domestic market;

(d) if so, whether Government propose to announce some incentives for the protection of industrial units presently engaged in the Ice-cream Manufacturing, with small capital investment; and

(e) if so, what are the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (e) Manufacture of ice cream is reserved for exclusive development in the small scale sector. As per the policy invogue the investment limit for ice cream industry is Rs. 60 lakhs i.e. the investment limit for SSI unit. As per the current policy there is no change in the investment limit for ice cream industry in the small scale sector.

आइसक्रीम उद्योग में पूंजी निवेश

3615. श्री मती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आइसक्रीम निर्माण के लिये वर्तमान पजी निवश की सीमा को बढ़ा कर 5 करोड़ रुपये कर देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं की स्थापना होगी;

(ग) यदि हां, तो इन बड़ी परियोजनाओं द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग कर कुल कितनी मात्रा में वार्षिक उत्पादन किये जाने की संभावना है और आइसक्रीम के उत्पादन के लिये एक परियोजना के मामले में कुल कितनी मात्रा में कच्चे दूध की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि चालू वर्ष तथा गत वर्षों के दौरान देश में आइसक्रीम के निर्माण में कुल दूध के उत्पादन में से औसतन कितने प्रतिशत दूध वार्षिक उपयोग किया जाता रहा है, यदि हां, तो यह मात्रा कितनी है ; और

(ङ) इस संबंध में तथ्य क्या हैं और क्या सरकार द्वारा आइसक्रीम निर्माण के क्षेत्र में बड़ी अतिरिक्त परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति देने के कारण देश में दूध की कमी होने तथा उसकी कीमतें बढ़ने के बारे में कोई अनुमान लगाया गया हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ङ) आइसक्रीम का निर्माण अनन्य विकास के लिये लघु क्षेत्र में आरक्षित है । मौजूदा नीति के अनुसार आइसक्रीम उद्योग अर्थात पस०एस०आई० यूनिट के लिये निवेश सीमा 60 लाख रु० है । वर्तमान नीति के अनुसार लघु क्षेत्र में आइसक्रीम उद्योग के लिये निवेश सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । सरकार ने देश में आइसक्रीम निर्माण के लिये दूध के प्रतिशत उपयोग तथा उसकी आपूर्ति पर प्रभाव संबंधी कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है । बहरहाल, अनुमान है कि कुल उत्पादन का 1% से कम आइसक्रीम निर्माण के लिये इस्तेमाल किया जाता है ।

Use of Hindi in the Ministry of Food Processing Industries

3616. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether his Ministry has chalked out any plans to promote the use of Hindi in its administration and other wings;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) what are the various schemes formulated and being implemented by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs issues instructions on the matter of use of Hindi and prepares various programmes, Plans and schemes like incentive scheme for original noting|drafting in official work, Grant of Incentive Allowance to stenographers and Typists for doing their official work in Hindi in addition to English, Incentives for writing original books in Hindi etc. for propogation of Hindi in various Ministries|Departments. These programmes, plans & schemes are implemented by this Ministry to the extent possible.

Plans to encourage food processing industry

3617. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what are the programmes and plans evolved by Government to encourage food processing industry;

(b) what is the State-wise number of food processing industries and which State tops the list in food processing industries in India; and

(c) what in the total exports from these food processing units under Government control from 1990 to 1994?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) The Government is encouraging establishment and expansion of food processing industries in the country, for which various policy measures and incentives including fiscal incentives have been provided. Besides Ministry is also implementng various plan schemes during the 8th Plan for the development of this sector.

(b) Since food processing industries are both in the organised and unorganised sector, information in regard to the number of food processing industries, Statewise, is not maintained centrally.

(c) While no export of food products have been made by the 2 Public Sector Undertakings, under the control of Ministry of Food Processing Industries, export of true potato seeds worth US $5250 have been made by the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati, under the control of this Ministry in the year 1994-95.